

PMAY-G और भारत में ग्रामीण नरिधनता उन्मूलन

प्रलमिस के लयि:

[प्रधानमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण](#), [नरिधनता](#), [जयि-टैगि](#), [सवचछ भारत मशिन ग्रामीण](#), [वशिव बैंक](#), [प्रधानमन्त्री ग्राम सडक योजना](#), [जल जीवन मशिन](#), [मनरेगा योजना](#), [लखपतदिदी](#), [मशिन इंदरधनुष](#), [बेरोजगारी](#), [गरीबी रेखा](#), [स्वयं -सहायता समूह](#)

मेन्स के लयि:

प्रधानमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण, ग्रामीण वकिस, ग्रामीण नरिधनता उन्मूलन ।

[स्रोत: पी.आई.बी](#)

चरचा में क्यौं?

ग्रामीण वकिस मंत्रालय ने **PMAY-G** की प्रगतपर प्रकाश डाला तथा ग्रामीण वकिस योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के माध्यम से **नरिधनता** मुक्त गाँव बनाने के प्रयासों पर बल दिया ।

- ग्रामीण वकिस योजनाओं का समय पर एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चति करके मंत्रालय का लक्ष्य नरिधनता मुक्त भारत का लक्ष्य प्राप्त करना है ।

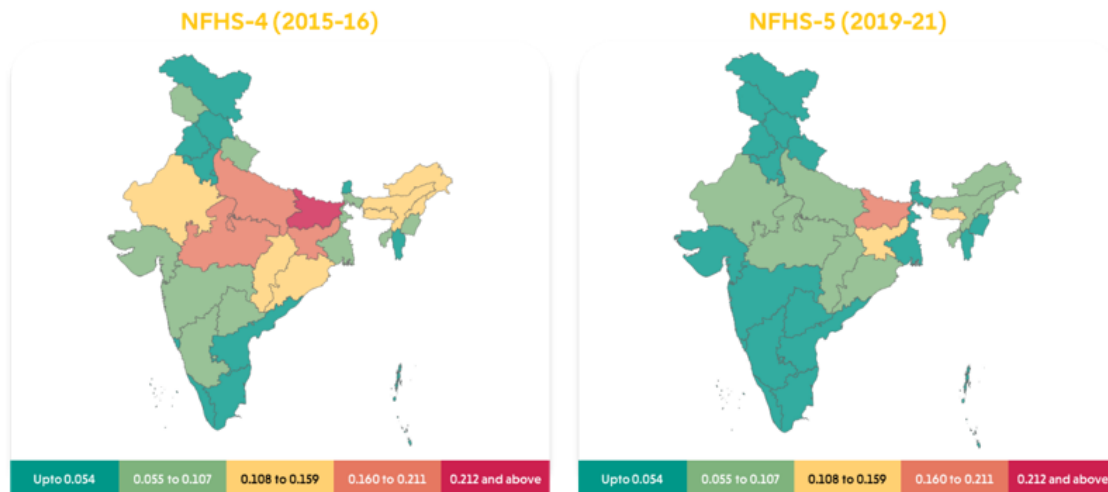
PMAY-G के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- यह ग्रामीण गरीबों को कफायती आवास उपलब्ध कराने के लयि **वर्ष 2016** में शुरू की गई योजना है। इसमें **लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक जातगित जनगणना (SECC) 2011** के आँकड़ों के आधार पर कयि जाता है, जसि **ग्राम सभा** की मंजूरी और **जयि-टैगि** के माध्यम से मान्य कयि जाता है ।
- **PMAY-G के अंतर्गत लाभ:**
 - **वत्तितीय सहायता:** मैदानी क्षेत्रों के लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपए तथा 2 पहाड़ी राज्यों (हमिचल प्रदेश और उत्तराखंड), पूरवोत्तर क्षेत्र एवं केंद्रशासति प्रदेशों (यूटी) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में 1.30 लाख रुपए दयि जाते हैं ।
 - लागत साझाकरण के संदर्भ में मैदानी क्षेत्रों में **60:40 (केंद्र और राज्य के बीच)** तथा पूरवोत्तर, हमिलयी राज्यों (हमिचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) तथा केंद्रशासति प्रदेश जम्मू और कश्मीर में **90:10 (केंद्र और राज्य के बीच)** का खर्च अनुपात शामिल है । केंद्रशासति प्रदेश लद्दाख में **100% केंद्र द्वारा वत्तिपोषति** कयि जाता है ।
 - **शौचालय सहायता:** **सवचछ भारत मशिन ग्रामीण (SBM-G)** के माध्यम से शौचालय नरिमाण के लयि 12,000 रुपए देना शामिल है ।
 - **खाना पकाने हेतु ईधन:** **प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना** के साथ मलिकर, प्रत्येक घर में एक LPG कनेक्शन प्रदान कयि जाता है ।
 - **रोजगार सहायता:** आवास नरिमाण के लयि **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम (MGNREGA)** के अंतर्गत 90/95 दविस का अकुशल कार्य दयि जाना शामिल है ।
- **लक्ष्यों का नरिधारण:** इस योजना में **अनुसूचति जाति(SC)** और **अनुसूचति जनजाति(ST)** परिवारों के लयि 60% का लक्ष्य नरिधारति है, जसिमें 59.58 लाख SC एवं 58.57 लाख ST से संबंधति आवास पूरे हो चुके हैं ।
- **योजना का वसितार:** इस योजना का लक्ष्य प्रारंभ में **वर्ष 2023-24 तक 2.95 करोड घरों का नरिमाण करना था**, जसि वत्ति वर्ष वर्ष 2024-29 के लयि 3,06,137 करोड रुपए के कुल परवियय के साथ **2 करोड और घरों को शामिल करने के लयि बढ़ा दयि गया है** ।
- **PMAY-G की उपलब्धतियाँ:** नवंबर 2024 तक **3.21 करोड घरों को मंजूरी दी जा चुकी है और 2.67 करोड घर पूरे हो चुके हैं** ।
 - **जून और दसिंबर 2024** के बीच **प्रधानमन्त्री जनजातिआदविसी न्याय महा अभयान (PM-JANMAN)** के तहत 71,000 सहति 4.19 लाख घर पूरे हो चुके हैं ।
 - **मोबाइल एप्लिकेशन:** लाभार्थी पहचान को कारगर बनाने के लयि **आवास प्लस-2024 ऐप** लॉन्च कयि गया ।
 - पारदर्शति और नगिरानी बढ़ाने के लयि **आवास सखी ऐप** शुरू कयि गया ।

नरिधनता

- **परचिय:** [वशिव बैंक](#) के अनुसार, नरिधनता बुनयिदी ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त आय या संसाधनों की कमी है। यह आवास, भोजन या स्वास्थय जैसे क्षेत्रों में अभाव के रूप में प्रकट हो सकती है।
 - नरिधनता का व्यापक दृष्टिकोण व्यक्ति की समाज में कार्य करने की क्षमता पर केंद्रित है, जिसमें आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, शक्ति और राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव शामिल है।
 - वशिव बैंक ने वर्ष 2017 [करय शक्ति समता \(PPP\)](#) का उपयोग करते हुए अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा के रूप में 2.15 अमेरिकी डॉलर को अपनाया, जो वर्ष 2011 PPP का उपयोग करते हुए वर्ष 2015 के अद्यतन में निर्धारित 1.90 अमेरिकी डॉलर से अधिक है।
- **पूर्ण नरिधनता:** ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति के पास भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य देखभाल जैसी बुनयिदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये संसाधनों का अभाव होता है, जिसे आमतौर पर गरीबी रेखा से मापा जाता है।
- **सापेक्ष नरिधनता:** समाज में अन्य लोगों की तुलना में किसी व्यक्ति के जीवन स्तर के आधार पर परिभाषित नरिधनता, जो आर्थिक असमानता को उजागर करती है।
- **भारत में नरिधनता के आँकड़े:** [राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 \(2019-21\)](#) के आँकड़ों से पता चलता है कि भारत की 14.96% आबादी बहुआयामी नरिधन है, जो [NFHS-4 \(2015-16\)](#) में 24.85% से कम है, जिसमें 135 मिलियन लोग नरिधनता से बच गए हैं।
 - [बहुआयामी गरीबी सूचकांक \(MPI\)](#) वर्ष 2013-14 में 29.17% से घटकर वर्ष 2022-23 में 11.28% हो गया है, जो 17.89% अंकों की कमी दर्शाता है।
 - [घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण \(HCES\)](#) से पता चलता है कि ग्रामीण नरिधनता वर्ष 2011-12 में 25.7% से घटकर वर्ष 2022-23 में 7.2% हो गई, जबकि शहरी नरिधनता इसी अवधि में 13.7% से घटकर 4.6% हो गई।

Comparative view of the Multidimensional Poverty Index Score (State/UT-wise)



The colour represents the MPI score of a state. The colour moves from green, through yellow, to red as the MPI score increases. Green represents areas with the lowest MPI scores while red represents areas with the highest MPI scores. The legend shows the range of MPI scores in India, based on the values for 2015-16. Both the comparative maps use the same legend to represent the change in MPI scores between 2015-16 to 2019-21.

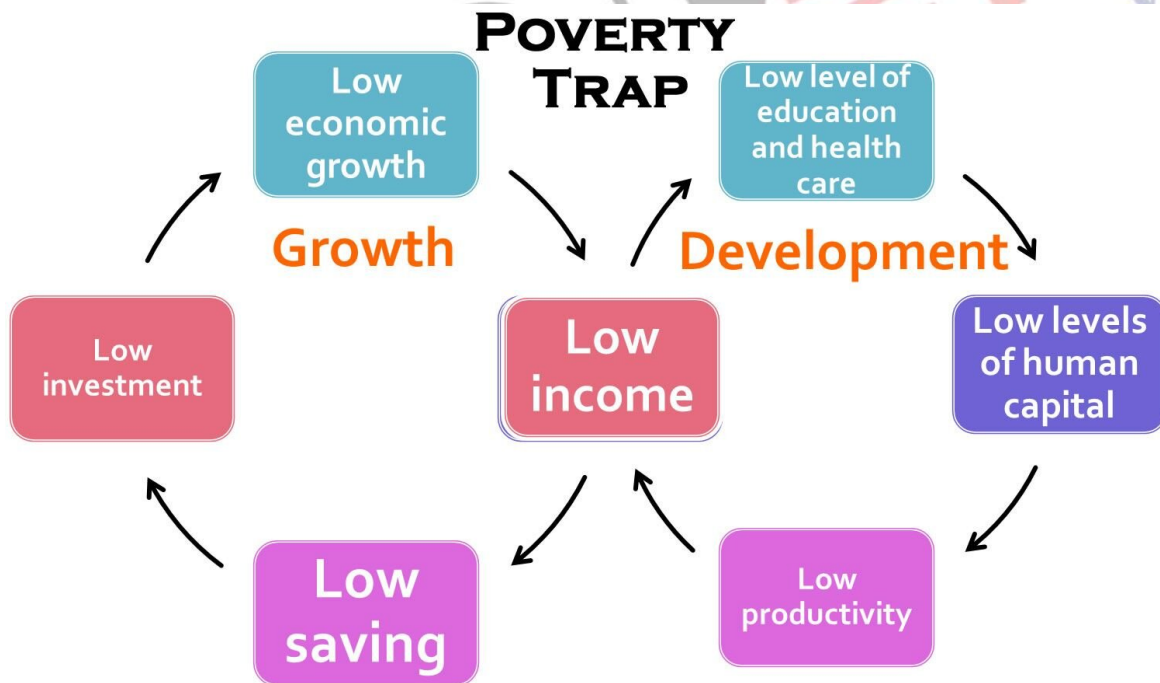
गाँवों में नरिधनता उन्मूलन में योगदान देने वाली अन्य योजनाएँ क्या हैं?

- आधारभूत संरचना:
 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)
 - जल जीवन मिशन
- सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:
 - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP)
 - जननी सुरक्षा योजना
 - प्रधानमंत्री जनधन योजना
 - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
 - प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- आजीविका संवर्द्धन योजनाएँ:
 - मनरेगा योजना
 - NRLM (राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन)

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- लखपति दीदी पहल
- स्वास्थ्य:
 - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत)
 - मशिन इंटरधनुष

ग्रामीण भारत में नरिधनता हटाने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- कृषिपर नरिभरता: ग्रामीण आबादी का एक बड़ा भाग कृषिपर नरिभर है, जसि जलवायु परिवर्तन, अनयिमति मानसून और खराब सचिआई जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- न्यूनतम कृषिउत्पादकता और पारंपरिक तरीकों पर नरिभरता आय सृजन को और सीमति कर देती है।
 - बेरोज़गारी और अल्परोज़गार: कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में रोज़गार के सीमति अवसर हैं, जसिके कारण बेरोज़गारी और अल्परोज़गार की दरें बहुत अधिक हैं। कौशल और शिक्षा की कमी के कारण यह और भी जटिल हो जाता है।
- सेवाओं तक सीमति पहुँच: शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और बुनियादी ढाँचे जैसी बुनियादी सेवाएँ प्रायः अपर्याप्त होती हैं।
- भूमि स्वामित्व: कई ग्रामीण परिवारों के पास भूमि स्वामित्व या सुरक्षित भूमि अधिकार का अभाव है, जसिसे आजीविका में नविश में बाधा आती है।
 - सामाजिक असमानता: महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों समेत हाशिये पर पड़े समुदायों को भेदभाव और संसाधनों तक सीमति पहुँच का सामना करना पड़ता है। इससे नरिधनता का चक्र चलता रहता है।
 - प्रवासन: कई युवा, शिक्षित व्यक्ति बेहतर अवसरों की तलाश में शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, जसिके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में "प्रतिभा पलायन" होता है।
- शासन संबंधी चुनौतियाँ: ऑपरेशन गरीबस योजना जैसी नीतियों का कमज़ोर कार्यान्वयन या भ्रष्टाचार, अपर्याप्त आँकड़े एवं सीमति सार्वजनिक जागरूकता ग्रामीण भारत में प्रभावी नरिधनता नविवरण में बाधा डालते हैं।
- दीर्घकालिक समाधानों के बजाय अल्पकालिक उपायों पर ध्यान केंद्रित करने से भी प्रगत में बाधा आती है।



ग्रामीण भारत को नरिधनता मुक्त कैसे बनाया जा सकता है?

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) प्राप्त करना:
 - नरिधनता उन्मूलन (SDG-1) सामाजिक सुरक्षा और रोज़गार।
 - सार्वजनिक वितरण प्रणाली और कृषियोजनाओं के माध्यम से शून्य भूख (SDG-2) खाद्य सुरक्षा।
 - आयुष्मान भारत के अंतरगत अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण (SDG-3) के लिये सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज।
 - असमानताओं में कमी (SDG-10) वित्तीय समावेशन और संसाधनों तक समान पहुँच में सुधार करती है।
 - सामाजिक संरक्षण और कल्याण: वृद्धावस्था, वधिया और वकिलांगता पेंशन के अंतरगत व्यापक कवरेज, 100% स्वास्थ्य देखभाल पहुँच और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवारों के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना ताकि नरिधनता को फेरि से बढ़ने से रोका जा

सके।

- **रोज़गार सृजन और आजीविका:** आवश्यकतानुसार मनरेगा के तहत रोज़गार उपलब्ध कराना, वार्ड और महिला सभाओं के माध्यम से कौशल संवर्द्धन आवश्यकताओं की पहचान करना तथा **ज़िला कौशल केंद्रों** के माध्यम से कौशल मानचित्रण और प्रशिक्षण आयोजित करना।
- **स्वयं सहायता समूहों और किसान समूहों को जोड़ना:** आय स्तर में सुधार के लिये **स्वयं सहायता समूहों (SHG)** और **किसान उत्पादक संगठनों (FPO)** को उद्यम योजनाओं के साथ एकीकृत करना।
 - किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिये **पशु मतिरों और किसान मतिरों** को सशक्त बनाना।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास:** विकास और सेवाओं तक बेहतर पहुँच को संकक्षम करने के लिये सड़कों, स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों का विकास करना।
- **डिजिटल समावेशन** के एक भाग के रूप में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों (जैसे, **राष्ट्रीय कृषि बाज़ार (ENAM)**) पर किसानों का **100% पंजीकरण** सुनिश्चित करना ताकि उन्हें योजनाओं तक वास्तविक समय पर पहुँच प्रदान की जा सके।
- **व्यवहारिक और सामाजिक परिवर्तन:** शोषणकारी शर्तों पर अनौपचारिक ऋण को सक्करिय रूप से हतोत्साहित करना। समुदाय के भीतरमादक द्रव्यों के सेवन के दुरुपयोग को संबोधित करना।
 - नरिणय लेने और आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
- **आपदा तैयारी और जलवायु कार्रवाई:** आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) के लिये एक **कार्यबल की स्थापना** करना और ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में गतिविधियों को एकीकृत करना।
 - **कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK)** के माध्यम से सतत कृषि और जलवायु-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना।

	100% eligible beneficiaries covered under old age, widow and disability pensions.		100% self-help groups (SHGs) and farmers groups are linked to enterprise schemes.
	100% access to services as per citizen's charter.		100% enrolment of households under public distribution system (PDS).
	100% coverage under Ayushman Bharat Yojana.		100% distribution of job cards to all applicants.
	100% registration of farmers on website: www.upagriculture.com		Continuous employment to all active job card holders as per demand under MGNREGA.



नर्षिकरषः

ग्रामीण भारत में नरिधनता उन्मूलन के लयिे आवास, वत्तितीय सहायता, रोज़गार और बुनियादी ढाँचे के विकास को मलिकर एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सतत् विकास, कौशल वृद्धि और वत्तितीय समावेशन के माध्यम से नरिधनता मुक्त गाँवों को प्राप्त करने के लयिे कृषि पर नरिभरता ने रोज़गारी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों का समाधान करना महत्त्वपूर्ण है।

???????? ???? ???? ???? ???? :

प्रश्नः नरिधनता उन्मूलन में ग्रामीण भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों तथा इन चुनौतियों पर काबू पाने में सरकारी पहल की भूमिका का आकलन करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????????

प्रश्न. नरिपेक्ष तथा प्रतियोगितावास्तविक GNP में वृद्धिआर्थिक विकास की ऊँची स्तर का संकेत नहीं करती, यदि: (2018)

- (a) औद्योगिक उत्पादन कृषिउत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।
- (b) कृषिउत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ-साथ बढ़ने में विफल रह जाता है।
- (c) नरिधनता और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है।
- (d) नरियात की अपेक्षा आयात तेज़ी से बढ़ता है।

उत्तर: (c)

प्रश्न. किसी दिये गए वर्ष में भारत के कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएँ अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं क्योंकि: (2019)

- (a) गरीबी की दर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।
- (b) कीमत- स्तर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
- (c) सकल राज्य उत्पाद अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है।
- (d) सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है।

उत्तर: (b)

प्रश्न. UNDP के समर्थन से 'ऑक्सफोर्ड नरिधनता एवं मानव विकास नेतृत्व' द्वारा विकसित 'बहुआयामी नरिधनता सूचकांक' में नमिनलखिति में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं? (2012)

1. पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, संपत्ति और सेवाओं से वंचन
2. राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति समता
3. राष्ट्रीय स्तर पर बजट घाटे की मात्रा और GDP की विकास दर

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

??????

प्रश्न. हालाँकि भारत में गरीबी के कई अलग-अलग अनुमान हैं, लेकिन सभी समय के साथ गरीबी के स्तर में कमी दर्शाते हैं। क्या आप सहमत हैं? शहरी एवं ग्रामीण गरीबी संकेतकों के संदर्भ में आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये (2015)